क्र० सं०	पंजीकरण संख्या	समिति का नाम	जमा धनराशि	जब्त की गई धनराशि	लौटाई जाने योग्य धनराशि
16	661	सेन्ट्रल वेयर हाऊस	15,00,000	15,00,000	*
17	691	नन्द्राजोग	47,83,000	33,83,833	13,99,167
18	653	उप निशद	16,51,650	14,03,053	2,48,597
19	786	नव संगम	20,25,000	14,03,053	6,21,947
20	687	होस्पिटल इंलाइज	22,00,000	12,37,988	9,62,012
21	599	साऊथ दिल्ली	13,00,000	9,07,858	3,92,142
22	754	वस्त्रलोक	25,00,000	17,33,183	2,66,817
23	612	ग्रीवस	49,06,250	26,41,040	22,65,210
24	877	श्री श्याम	41,56,250	—	4,56,250
25	913	नव सिद्धार्थ	23,28,125	—	23,28,125
26	918	परम आशीर्वाद	29,85,000	—	29,85,000
27	979	परियोजना	18,40,625	—	18,40,625

*इस सोसायटी से 24,75,975 रुपये जब्त किये जाने थे, परंतु चूंकि इस सोसायटी ने मात्र 15,00,000 रुपये ही जमा कराये थे इसलिये यही राशि जब्त की जानी है।

Mandoosi Menace

@4034. SHRI S. S. SURJEWALA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the current wheat crop in the Northern parts of the country, particularly in Haryana and Punjab, is being threatened by the growth of Mandoosi (Weed), which is likely to result in fall in the production of wheat;

(b) whether Government are also aware that the weedicide which the farmers purchase both from the private dealers as well as from Government agencies like Agro Industries/Corporations in the above States, have failed to destroy the Mandoosi (Weed) ;

(c) whether the matter has been enquired into by Government for this ineffectiveness of such weedicides and the requisite punishment imposed on such agencies; and

(d) what is the necessary compensation provided to farmers due to this loss of crops ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) The Government is aware that the Mandoosi weed technically known as *Phalaria minor* is a major weed of wheat crop in the northern parts of the country particularly in Haryana and Punjab. The production of wheat is not likely to fall in these States since the control measures weed quite effective.

(b) and (c) The use of Isoproturon weedicide, distributed through the Government agencies has given satisfactory control of *Phalaria minor* in these States. Insufficient moisture in the soil, improper and untimely application of weedicides and burning of paddy straw in the wheat fields reduces the efficacy of Isoproturon.

(d) Question does not arise.

@Previously Unstarred Question No. 3031, transferred from 17th March, 1994.

उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में कार्यरत सहकारी-संगठन

4035. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कृषि-क्षेत्र में कितने सहकारी-संगठन कार्य कर रहे हैं;

(ख) पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इन सहकारी संगठनों को केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित की गई धनराशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) से (ग) इस विषय पर विस्तृत सूचना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

पान की खेती के विकास हेतु अनुसंधान केन्द्र

4036. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में पान की खेती के विकास के लिए अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की है और यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इन केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में ऐसे केन्द्र स्थापित किए गए हैं; क्योंकि यह राज्य पान के उत्पादन में सबसे आगे है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य को लघु तथा सीमांत कृषकों को पान के उत्पादन हेतु केन्द्र द्वारा वित्तपोषित पान विकास योजना के अन्तर्गत अब तक वर्ष-वार कितनी अनुदान-राशि प्रदान की है और यह अनुदान किस आधार पर दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) जी, हां । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाएं चलाती है जिसके तहत राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में समन्वयक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये गये हैं जो असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में स्थित हैं ।

(ख) मध्य प्रदेश में जबलपुर केन्द्र वर्ष 1981 से ही कार्य कर रहा है ।

(ग) आठवीं योजना में स्वीकृत केन्द्रीय क्षेत्र योजना के प्रावधानों के आधार पर मध्य प्रदेश को अनुदान रिलीज किया गया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1991-92	1992-93 (रु० लाख में)	1993-94 (रु० लाख में)
शून्य	1.28	3.375

"सब्जी मिनी किट प्रदर्शन" योजना

4037. श्री शिवप्रसाद चनपुरिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा प्रायोजित "सब्जी मिनी किट प्रदर्शन" योजना के अन्तर्गत शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में कितनी धन राशि दी गई है; और

(ख) मध्य प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या-क्या हैं, जहां इस अनुदान-राशि का प्रयोग करके सब्जी मिनी किट वितरित किए गए और वर्ष 1992-93 के दौरान वहां सब्जी का कितना उत्पादन हुआ था ?

कृषि में मंत्रालयराज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) सब्जियों के बीजों के उत्पादन तथा सप्लाई की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार ने 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को सब्जियों के बीजों के मिनि किटों के वितरण के लिए 9.00 लाख रुपये का शत-प्रतिशत अनुदान दिया है ।

(ख) उक्त राशि में से मध्य प्रदेश के जिन जिलों में सब्जियों के बीजों के मिनि किट वितरीत किए गए, उनके नाम विवरण में दिए गए है । **(नीचे देखिए)** इन मिनि किटों के वितरण के फलस्वरूप 1992-93 में 9573 मीटरी टन सब्जियों का अतिरिक्त उत्पादन हुआ ।

विवरण

मध्य प्रदेश के वे जिले जिनमें 1992-93 के दौरान सब्जिओं के बीजों के मिनि किट वितरित किए गए ।

1. बस्तर
2. रायपुर
3. दुर्ग
4. राजनांदगांव
5. बिलासपुर
6. रायगढ़
7. अम्बिकापुर
8. जबलपुर
9. नरसिंहपुर
10. सिवनी
11. बालाघाट
12. मंडला
13. छिन्दवाडा
14. रीवां
15. शहडोल
16. ग्वालियर
17. शिवपुरी
18. गुना
19. दतिया
20. भिण्ड
21. मुरैना
22. सागर
23. पन्ना
24. छत्तरपुर
25. टीकमगढ़
26. दमोह
27. भोपाल
28. सीहोर
29. रायसेन
30. विदिशा
31. बैतूल
32. राजगढ़
33. होशंगाबाद
34. इन्दौर
35. धार
36. झाबुआ
37. खरगोन
38. खण्डवा
39. उज्जैन